



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]
No. 202]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2003/श्रावण 31, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2003/SRAVANA 31, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय .

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2003

विषय : यूएसए, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्रोपाइलीन ग्लाइकोल के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/8/2003-डीजीएडी.—मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमि., चैन्नै ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें यू एस ए, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्रोपाइलीन ग्लाइकोल के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद प्रोपाइलीन ग्लाइकोल सभी ग्रेड हैं। इसका विनिर्माण उच्च दबाव और तापमान पर उत्पाद के द्रवीकरण द्वारा प्रोपाइलीन आक्साइड से किया जाता है जिससे मोनो, डाइ और ट्राइ-प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का मिश्रण तैयार होता है। मोनो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल (एम पी जी) जिसे आमतौर पर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल के रूप में माना जाता है, एक प्रमुख उत्पाद है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का उपयोग पालिस्टर रेजिन के विनिर्माण, औद्योगिक प्रशीतन रोधी अनुप्रयोगों जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों तथा भेषज उद्योगों में किया जाता है। यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ कोड 29053200 के अंतर्गत वर्गीकृत है। जांच विचाराधीन उत्पाद के बारे में शुरु की जा रही है; भले ही जिस वर्गीकरण के अंतर्गत उसका आयात किया जा रहा है वह कुछ भी हो। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह याचिका मै0 मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि0, चैन्नै द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है और इस प्रकार उसके पास नियम 2 (ख) के साथ पठित

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (3) (क) के अनुसार याचिका दायर करने का आधार है।

3. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश/ क्षेत्र यू एस ए , सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ हैं (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है।)

4. समान वस्तुएं

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तुएं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों वस्तुएं तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तुएं माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों / क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा उद्गम के देशों में उत्पादन लागत के आधार पर किया है। अनुमानित सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर निकाला गया है तथा लागत के अन्य तत्वों का अनुमान याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार उचित लाभ जोड़ने के पश्चात् उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर यू एस ए, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूरोपीय संघ में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य को प्रथम दृष्टया स्वीकार किया है।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से निर्यात की कीमत का निर्धारण सौदेवार सूचना, जो आंकड़ों के गौण स्रोतों अर्थात् मै0 इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, जिनके आंकड़े सीमा शुल्क दैनिक सूची पर आधारित हैं, से ली गई है, के अनुसार निर्धारित किया है। कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

7. पाटन मार्जिन

इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों के संबद्ध में सूचना प्रस्तुत की है। संबंध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि, आयात कीमत में गिरावट, कुल मांग के संबंध में संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि, याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट, धरेलू बिक्री में कमी, निवेश में कम आय, लाभप्रदता में गिरावट, नकारात्मक नकदी प्रवाह, कीमत कटौती और कीमत ह्रास जैसे अन्य मापदण्डों से सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण धरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

9. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की है।

11. सूचना देना

इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त नियम के नियम 6 (5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति और कारणात्मकता के संबंध में जांच के लिए अनिवार्य सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल. वी. सप्तर्षि, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2003

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigations concerning Import of Propylene Glycol originating in or exported from USA, Singapore, Korea RP and European Union.

No. 14/8/2003-DGAD.—M/s. Manali Petrochemicals Limited, Chennai, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Propylene Glycol originating in or exported from USA, Singapore, Korea RP and European Union and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under investigation in the present case is Propylene Glycol – All grades. It is manufactured from Propylene Oxide by hydrating the product at a higher pressure and temperature which form a mixture of Mono, Di and Tri-Propylene Glycol. Mono-Propylene Glycol (MPG), generally known Propylene glycol is the principal product. The Propylene Glycol is used for industrial applications like manufacture of polyester resin, industrial anti-freezing applications and in pharmaceutical industries. This product is classified under Customs Tariffs Code 29053200. Investigations are being initiated with respect to product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of investigations.

2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The petition has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited, Chennai. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India and hence has standing to file the petition in terms of Rules 5(3) a of the Rules supra read with Rule 2(b).

3. COUNTRIES INVOLVED

The countries/territory involved in the present investigation are USA, Singapore, Korea RP and European Union. (Hereinafter also referred to as subject countries).

4. LIKE GOODS

The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles of the product imported from the subject country within the meaning of the Rules, supra.

5. NORMAL VALUE

The petitioner has claimed normal value of subject goods in the subject countries/territory on the basis of cost of production in the countries of origin. The estimated normal value has been arrived at on the basis of international price of raw materials and other elements of the cost has been estimated on the basis of data available with the petitioner. The Authority has prima facie accepted the normal value of the subject goods in the USA, Korea RP, Singapore and European Union on the basis of constructed cost of production after addition of selling, general and administrative expenses along with reasonable profit as per data made available by petitioner.

6. EXPORT PRICE

The Petitioner has determined the export price from the subject countries based on the transaction wise information, which is culled from the secondary data sources, i.e. M/s International Publishing House, Mumbai whose data is based on the Customs Daily List. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level.

7. DUMPING MARGIN

2371 GI/03-2

There is, prima facie, submitted evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioner has furnished information on various parameters relating to injury. Parameters such as increase in volume of imports from subject countries, decline in the import prices, rise in the share of the subject countries in relation to total demand, decline in the markets share of the petitioner, reduction in the domestic sales, low return on investment, decline in the profitability, negative cash flow, price undercutting and price underselling, prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

10. PERIOD OF INVESTIGATION

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation 1st April 2002 to 31st march 2003.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.